सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 201 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 29 अगस्त, 2026
मूल्य ₹ 3/-

जहां जाइये प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आये वह और खुश होकर लौटे।
-मदर टेरेसा

जापान में सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है... 7 | भाजपा एकबार फिर चुनावी मोड... 3 | भाजपा सिर्फ वादा खिलाफी करती... 2

जियो आईपीओ नाम बड़ा तो सवाल बड़े!

52 करोड़ ग्राहकों की ताकत, घटते कर्मचारी जीरो डिविडेंड और एआई के सपने

» निवेशक पैसा लगाने से पहले हिसाब जरूर पूछें
» पैसा भावना से नहीं, हिसाब सवाल पूछकर लगाएं

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जियो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहक? देश का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क? मुकेश अंबानी? 5जी? एआई? या फिर वह कंपनी जिसने 2020 में दुनिया के बड़े-बड़े टेक दिग्गजों को अपने दरवाजे तक खींच लिया था। अगर इनमें से कुछ भी आपके दिमाग में आया है तो जरा रुकिए। क्योंकि अब उसी जियो के दरवाजे पर आपका पैसा दस्तक देने वाला है। और इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जियो कितना बड़ा है।

सवाल यह है कि आपका पैसा जियो के पास क्यों जा रहा है? कहां जाएगा? और उसके बदले आपको मिलेगा क्या? सेबी ने जियो प्लेटफार्मस के प्रस्तावित आईपीओ के लिए रास्ता साफ कर दिया है। प्रस्तावित इश्यू का आकार करीब 37,700 करोड़ तक पहुंच सकता है और यह भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। जियो प्लेटफार्मस करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी करने की तैयारी में है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह संख्या है जिसे विज्ञापनों की चमक में शायद सबसे पीछे रखा जाए 27, 500 करोड़। यही वह रकम है जिसे कंपनी रिलायंस जियो इंफोकाम के पुराने कर्ज को चुकाने या प्रीपे करने में इस्तेमाल कर सकती है?

क्या कर्ज चुकाने में जाएगी बड़ी रकम?

जानकारों के मुताबिक आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम का बड़ा हिस्सा रिलायंस जियो इंफोकाम के कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल होने की योजना है। इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत है। कर्ज चुकाना कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। लेकिन निवेशक को यह जरूर समझना चाहिए कि वह जिस आईपीओ को नई ग्रोथ में निवेश समझकर देख रहा है उसके क्रियान्वन का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने/कर्ज घटाने में जाने वाला प्रस्तावित है।

सवाल पूछना, सवाल उठाना गुनाह नहीं

सवाल पूछना गुनाह नहीं है सवाल उठाना जुर्म नहीं है अब सवाल यह है कि अगर जियो का भविष्य इतना सुनहरा है अगर एआई, क्लाउड, 5जी और डिजिटल इंडिया की अगली क्रांति जियो के दरवाजे पर खड़ी है अगर कंपनी के पास 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का विशाल आधार है तो फिर आईपीओ से जुटाए जाने वाले हजारों करोड़ में इतनी बड़ी रकम पुराने कर्ज को चुकाने में क्यों प्रस्तावित की जा रही है? क्या यह नई छलांग की तैयारी है? क्या यह बैलेंस शीट को और मजबूत करने की रणनीति है? या निवेशक से जुटाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद वित्तीय बोझ को हल्का करने में जाएगा? जवाब कंपनी के दस्तावेजों में है लेकिन सवाल निवेशक को खुद पूछना होगा। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि आईपीओ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। आईपीओ में आप कंपनी का नाम नहीं खरीदते आप उसके भविष्य की कीमत चुकाते हैं। रिलायंस बहुत बड़ा नाम है जियो बहुत बड़ा नाम है ग्राहकों का बेस बहुत बड़ा है नेटवर्क बहुत बड़ा है एआई की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है तो इन सब के साथ निवेशक का पहला सवाल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए कि कंपनी कमाती कितना है और मेरे पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे करेगी?

क्या भारतीय निवेशक के हाथ में आयेगा जियो प्लेटफार्मस?

2020 को याद कीजिए उस समय जियो ने आईपीओ नहीं निकाला था। जियो प्लेटफार्म ने ग्लोबल इक्वैस्टर से 1.52 लाख करोड़ जुटाए थे। फेसबुक यानी मेटा, गूगल और दुनिया के बड़े निवेशकों ने जियो प्लेटफार्मस में पैसा लगाया। रिलायंस ने इसे अपने डिजिटल कारोबार की ताकत और भविष्य के विश्वास की बड़ी मिसाल के तौर पर पेश किया। अब छह साल बाद कहानी का अगला एपीसोड जनता के पैसों को आईपीओ के जरिये निवेश के तौर पर सामने हाजिर होने वाला है। और यही फर्क बेहद महत्वपूर्ण है। 2020 में रणनीतिक और वित्तीय निवेशक जियो प्लेटफार्मस में हिस्सेदारी खरीद रहे थे। अब खुदरा निवेशक भी जियो के शेयर का मालिक बनने की दौड़ में शामिल होने वाले हैं। यानी जियो की कहानी अब सिर्फ ग्लोबल इक्वैस्टर के कमरे में तय नहीं होगी बल्कि उसका एक हिस्सा आम भारतीय निवेशक के हाथ में भी जाएगा।

निवेशक के सामने सबसे बड़ा खतरा इंपल्स बाइंग का है?

इंपल्स बाइंग मतलब जर्बदस्ती खरीदारी। मग के साथ बाल्टी फ्री, मोजे के साथ जूते फ्री इस तरह के ऑफर सुपर मार्केट में देखने को मिलते हैं और ऑफर देखकर खरीदारी करने गया आम परिवार आटा दाल खरीदने क बजाए बाल्टी और जूते खरीद कर वापस आ जाता है जिसकी उसे जरूरत नहीं। कहीं कुछ ऐसा ही आने वाले दिनो में भारतीय शेयर बाजारों में भी तो देखने को नहीं मिलने वाला जिसकी संभावना 100 फीसदी है। क्योंकि जिस कंपनी के शेयर आने वाले हैं उस कांपनी का मीडिया पर कब्जा है। खुद के दर्जनो चैनल के साथ उसका दखल दूसरे मीडिया संस्थानों में भी है ऐसे में टीवी पर विशेषज्ञों की बहस होगी सोशल मीडिया पर जियो का शेयर नहीं लिया तो क्या लिया जैसा माहौल बनाए जाने की प्रबल संभावना है ऐसा एक्सपर्ट का कहना है।

संबंधित खबर पेज 8 पर

एक्सपर्ट की नजर में यहीं रुकना चाहिए

पैसा भावना से नहीं हिसाब देखकर लगाया जाता है। क्योंकि आईपीओ के समय कहानी हमेशा भविष्य की होती है। कंपनी बताएगी कि वह अगले पांच साल में क्या करेगी। बाजार बताएगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। विशेषज्ञ बताएंगे कि यह ऐतिहासिक मौका है। विज्ञापन आपको बताएंगे कि डिजिटल इंडिया का अगला युग आने वाला है। लेकिन निवेशक को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए कि आज की कीमत कितनी है? क्योंकि 100 रुपये की चीज अगर 500 रुपये में बेची जा रही है तो सिर्फ इसलिए वह सस्ती नहीं हो जाती कि दुकान पर रिलायंस का बोर्ड लगा है। अभी जियो प्लेटफार्मस के आईपीओ की अंतिम कीमत तय नहीं हुई है। प्रस्तावित इश्यू का मूल्यांकन करीब 9.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की चर्चाओं में है और अंतिम कीमत बुक बिल्डिंग के जरिए तय होगी। यानी असली परीक्षा तब होगी जब प्राइस बैंड सामने आएगा।

इसलिए सवाल अभी से तैयार रखिए

क्या जियो की कीमत उसकी कमाई के हिसाब से उचित होगी? या फिर निवेशक से कहा जाएगा कि भविष्य देखिए? भविष्य जरूर देखिए लेकिन बैलेंस शीट साथ लेकर और अब आइए उस सवाल पर जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह है डिविडेंड। आखिर जियो प्लेटफार्मस ने अपने गठन के बाद से अपने सामान्य शेयरों पर घोषित लाभांश का भुगतान क्यों नहीं किया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जियो प्लेटफार्मस खराब कंपनी है या उसका शेयर खरीदना गलत है। ऐसा निष्कर्ष निकालना गैर जिम्मेदाराना होगा। कंपनियां कई बार मुनाफे को कारोबार के विस्तार में लगाती हैं और रलाभांश नहीं देतीं। लेकिन सवाल पूछना तो बनता है। अगर कंपनी सार्वजनिक बाजार में उतरकर आम निवेशक से पैसा लेने जा रही है तो निवेशक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कंपनी मुनाफे को किस तरह इस्तेमाल करेगी।

भाजपा सिर्फ वादा खिलाफी करती है : अखिलेश यादव

» सपा प्रमुख बोले- मुफ्त बस का वादा कर बसें हटवाईं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर करारा प्रहार जारी है। सपा प्रमुख ने रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मुफ्त यात्रा का वादा किया, लेकिन बसें हटा दीं। सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर वादा खिलाफी और सिर्फ वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। जाट समाज के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का वादा तो किया, लेकिन बसें ही हटवा दीं।

अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए कहने वाले रघुवंशियों तक को ठग लेने वाले ये भाजपा नेता क्या वचन निभाएंगे। उन्होंने जाट समाज से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जाट समाज में व्याप्त आक्रोश और मारे गए लोकप्रिय युवा गायक अंकित बालियान के दुखी पिता की बात सुनेंगे या उनसे भी उसी तरह पेश आएंगे, जैसा पहले एक दुखी मां के साथ हुआ था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ वोटों की सगी है, जाट या किसी अन्य समाज की नहीं। उन्होंने कहा कि आज जो जाट नेता अपने स्वार्थ के कारण भाजपा के साथ खड़े हैं, उनसे पूरा जाट समाज जवाब मांग रहा है। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि भाजपा के सहयोगी जाट नेता आखिर कहां भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि युवा जाट आज ऐसे नेताओं को तलाश रहे हैं और उनसे जवाब मांगना चाहते हैं।

जेपीएनआईसी को जितने में बेचा, उतना पैसा पार्किंग से आ जाएगा

अखिलेश ने कहा कि मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से जेपीएनआईसी और उसके पूरे क्षेत्र की कीमत छह हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने इसे जितने में बेचा है, उतनी रकम 30 साल की पार्किंग से ही वसूल हो सकती है। उनके अनुसार पार्किंग से 30 वर्षों में करीब 867 करोड़ रुपये की आय होगी। उन्होंने कहा कि समय आने पर जेपीएनआईसी की बिक्री की पूरी जांच होगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अखिलेश ने किसान बाजार, शाने-अवध, जनेश्वर मिश्र पार्क और शहीद पथ स्थित मॉल के कुछ हिस्सों की बिक्री का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा सरकार की परियोजनाओं को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए।

कांग्रेस पार्टी जरुरतमंदों के साथ खड़ी : अजय राय

» प्रदेश अध्यक्ष ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों से राखी बंधवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पूर्व मंत्री ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज वृंदावन कालोनी स्थित पाल मर्सी होम मे मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर बच्चियों ने राखी बांधकर उनके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा की यहाँ आना उनके लिए बहुत सुखद अनुभव है. उन्होंने पाल मर्सी होम द्वारा किये जा रहे इस पुनीत कार्य की सराहना की। पाल मर्सी होम में मानसिक अस्वस्थ और यौन हिंसा से पीड़ित एवं जरूरतमंद बच्चियों की देखभाल की जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह यहाँ दूसरी बार आये है, बेसहारा बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर स्वयं व कांग्रेस पार्टी की और से मदद की जायेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बच्चियों की बेहतर सेवा व देखभाल के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे।

सैनी सरकार में कानून व्यवस्था फेल और वादें हैंअधूरे : कुमारी सैलजा

» कांग्रेस नेता का भाजपा पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार में कथित आंतरिक कलह, कानून व्यवस्था और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। साथ ही सैलजा ने सरकार पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के भीतर आपसी खींचतान की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय राजनीतिक खींचतान दिखाई दे रही है। कांग्रेस सांसद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम लोगों के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल में करने का अवसर

मिलना चाहिए। सैलजा ने भाजपा सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ सरकार को चुना था, उन पर सरकार खरा उतरने में विफल रही है। कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली से नियंत्रित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फैसले स्थानीय जरूरतों और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। सैलजा ने भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत करने, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की।

जयंत की नजर संगठन विस्तार पर

» कल राजधानी आएंगे रालोद अध्यक्ष

» संगठन विस्तार और ब्राह्मण-सवर्ण समाज को जोड़ने की रणनीति पर वह करेंगे काम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी का लखनऊ का दौरा करेंगे। 27 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार और ब्राह्मण-सवर्ण समाज को जोड़ने की रणनीति पर वह काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह 30 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनकी मौजूदगी में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक एवं विचार-विमर्श बैठक आयोजित की जाएगी।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। लोकदल लगातार समाज के विभिन्न वर्गों को संगठन से जोड़ रहा है। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के बीच पार्टी की विचारधारा और चौधरी चरण सिंह के सामाजिक न्याय, किसान हित राजनीति को लेकर सकारात्मक वातावरण बना है। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के साथ-साथ सवर्ण समाज के कई प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक चेहरे राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में मानसून के मौसम में राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है। 27 नजदीक आते ही प्रदेश के ब्राह्मण राजनीति के केंद्र में फिर आते दिख रहे हैं। पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ पीडीए की राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। समय-समय पर पीडीए की तमाम परिभाषाएं बताने वाले सपा मुखिया ने अब पीडीए के पीडी को पंडित बताया है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

कार्यकर्ताओं के परिवारों को डराया जा रहा : डोटासरा

राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। निकाय चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारों की फोज खड़ी है। ऐसे में सूची जारी होने से बगावत का बड़ा खतरा बन रहता है। शहरी चुनाव पूरी तरह स्थानीय समीकरण पर निर्भर रहते हैं इसलिए बागी निर्दलीय खड़े होकर भी खेल बिगाड़ सकते हैं।

कांग्रेस की इस रणनीति से टिकट को लेकर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहेगा। दावेदारों को यह पता नहीं चलेगा कि पार्टी ने किस नाम को अंतिम मंजूरी दी है, जब

तक जिला संगठन की ओर से उन्हें इसकी सूचना नहीं दी जाती।

निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस ने एक और अहम गाइडलाइन लागू की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि दावेदार जिस वार्ड का निवासी है, वह उसी वार्ड से टिकट के लिए आवेदन कर सकेगा। दूसरे वार्ड से की गई दावेदारी पर पार्टी विचार नहीं करेगी। अब देखना होगा कि यह रणनीति पार्टी के भीतर असंतोष को कम करने में कितनी कारगर साबित होती है और जिलों में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस कितनी तेजी से अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में सक्रिय कर पाती है।

भाजपा एकबार फिर चुनावी मोड में आई

बंगाल में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी शुरू

» पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने का दावा
» बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल संभव
» कांग्रेस, टीएमसी व अन्य दलों को चुनौती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भाजपा एकबार फिर चुनावी मोड में आने लगी है। जहां वह पंजाब में विस चुनाव की तैयारी में जुट गई है वहीं पश्चिम बंगाल 26 के कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनावों के लिए अपनी संगठनात्मक तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार को कोलकाता का प्रभारी और राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को हावड़ा का प्रभारी नियुक्त किया है, जो आगामी चुनावों के लिए मजबूत नेतृत्व और चुनावी रणनीति बनाने पर जोर देता है। इन नियुक्तियों से बीजेपी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है।

इस बीच कार्यसमिति में बदलाव के बाद सरकार में बदलाव पर काम शुरू हो गया। पार्टी के एक संगठनात्मक सर्कुलर के अनुसार, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता और हावड़ा में 26 के नगर निगम चुनावों की देखरेख के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार को कोलकाता नगर निगम चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है, और राज्य के उपाध्यक्ष अनिंद्य बनर्जी (राजू) को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री तापस रॉय को कोलकाता चुनावों के लिए संयोजक बनाया गया है, और काशीपुर-बेलगाछिया से विधायक रितेश तिवारी को सह-संयोजक नियुक्त किया गया है। इन्ही तैयारियों के भाजपा ने कांग्रेस, टीएमसी व अन्य दलों को चुनौती देना शुरूकर दिया है।

फूलका ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की

वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता एच एस फूलका ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई एक अहम संगठनात्मक बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से बात की। फूलका ने पंजाब में बीजेपी की संभावनाओं पर भरोसा जताया और दिवंगत पूर्व सांसद सज्जन कुमार से जुड़े कानूनी मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में फूलका ने कहा कि आज बीएल संतोष ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जमीनी स्तर की सभी रिपोर्टों की समीक्षा की और आगामी चुनावों के लिए हमारी भूमिकाओं पर चर्चा की। यह बहुत उत्साहपूर्ण और सार्थक बैठक थी। बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों में पंजाब में सरकार बनाएगी।

हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए, राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को इंचार्ज

हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए, राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को इंचार्ज और बाली के विधायक संजय कुमार सिंह को कन्वेनर नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कीं और ये तुरंत लागू हो गई हैं। इसके अलावा, 25 अगस्त को सुकांत मजूमदार ने बीजेपी नेता सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव दोबारा नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। एक पोस्ट में मजूमदार ने कहा कि आज भाजपा बंगाल के राज्य कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर दोबारा नियुक्ति के लिए सम्मानित सुनिल बंसल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। संगठन में नई ऊर्जा और मजबूती लाने में उनका नेतृत्व निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा। उनके सफल कार्यकाल और उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये नियुक्तियां पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले बीजेपी की अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिशों को दर्शाती हैं।

शिअद का नेताओं को ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारी न मांगने का निर्देश

शिरोमणि अकाली दल (शिअउ) के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच, संतोष ने सोमवार को कहा था कि भाजपा पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 27 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। इस बीच, सूत्रों का कहना है कि बीजेपी व शिअद 27 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन को फिर से शुरू करने की बातचीत के अंतिम चरण में हैं, जिसमें शिअद के मुख्य सहयोगी (सीनियर पार्टनर) होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, सीट-शेयरिंग पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और सैड-शिअद ने अपने नेताओं को ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवारी न मांगने का निर्देश दिया है।

यह बोर्ड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश भी करेगा

न प्रस्तावित बदलावों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बोर्ड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। कई राज्यों में 27 और 28 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके बाद 29 में लोकसभा चुनाव होंगे। सूत्रों का अनुमान है कि बोर्ड में तीन से चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और उनमें से किसी एक के लिए जगह बनाने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा को हटाया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी बातचीत चल रही है। मौजूदा बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नड्डा शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाएगा। नए सिरे से गठित होने वाली इस बॉडी में दक्षिण भारत के किसी नेता को भी जगह मिल सकती है। फडणवीस इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वे आरएसएस से गहराई से जुड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस उन्हें केंद्रीय राजनीति में एक युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ते देखना चाहती है। अभी महाराष्ट्र से संसदीय बोर्ड में कोई प्रतिनिधि नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कभी इसके सदस्य हुआ करते थे।

29 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के नेतृत्व को आकार देने की तैयारी

बीजेपी अपने सर्वोच्च निकाय, संसदीय बोर्ड, में महत्वपूर्ण फेरबदल की तैयारी में है, जिसमें तीन-चार मुख्यमंत्रियों और युवा नेताओं को शामिल किया जा सकता है। यह कदम 29 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के नेतृत्व को आकार देने के लिए अहम माना जा रहा है, खासकर देवेंद्र फडणवीस जैसे आरएसएस समर्थित नेताओं के राष्ट्रीय राजनीति में उदय की संभावना है। बीजेपी अपने 12 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड में 30 अगस्त के आस-पास बदलाव कर सकती है। इसमें युवा नेताओं और तीन-चार मौजूदा मुख्यमंत्रियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों - योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा सरमा - के नामों पर भी चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी का नाम भी चर्चा में है।

ड्रग्स की समस्या को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने पर बल : पूनिया

पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने का स्पष्ट इरादा जताया है। पार्टी प्रभारी सतीश पूनिया ने अपनी ताकतों व नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए ड्रग्स की समस्या को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने पर बल दिया, जो राज्य की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी पंजाब के प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पंजाब विधानसभा के आगामी चुनावों में जीत के मकसद से सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए, पूनिया ने पार्टी की अपनी ताकतों और नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और पंजाब के सामने मौजूद ड्रग्स

की समस्या को एक अहम मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मकसद जीतना होगा... बीजेपी अपनी ताकतों और नीतियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है; हम निश्चित रूप से 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा एकमात्र मकसद जीतना होगा। पूनिया ने पंजाब को एक ऐसा राज्य बताया जिसे कभी अपने युवाओं, खिलाड़ियों, परंपराओं, शांति, समृद्धि और हरियाली के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता था, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ड्रग्स ने राज्य की अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर कितना बुरा असर डाला है। पूनिया ने कहा कि इसलिए, हम युवाओं और नागरिक समाज से अपील करते हैं कि वे ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एकजुट हों और इस अभियान को सफल बनाएं।

फडणवीस की नियुक्ति को लेकर कुछ आपत्तियां और आशंकाएं

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी किसी भी राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री बीजेपी के संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं है। इसलिए, कुछ नेताओं को देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति को लेकर कुछ आपत्तियां और आशंकाएं हैं। हालांकि, एक अन्य नेता ने कहा कि अगर फडणवीस को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में जगह मिलती है, तो इससे उनके राष्ट्रीय राजनीति में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि नितिन गडकरी के बाद फडणवीस संघ के चहेते नेता हैं। इस फेरबदल के संगठनात्मक असर भी होंगे। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव की संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और युवा नेताओं को

शामिल किया जा सकता है। बीजेपी ने पहले भी संसदीय बोर्ड का इस्तेमाल भविष्य के नेतृत्व का संकेत देने के लिए किया है। तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री मोदी को 2006 में राजनाथ सिंह ने बोर्ड से हटा दिया था, लेकिन 13 में उन्हें फिर से शामिल कर लिया गया - यानी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किए जाने से एक साल पहले।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

पलायन को रोकने से होगा मानव कल्याण

“ महाराष्ट्र सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उससे भी ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी उन राज्यों की है जिनके लोग अपने राज्य में रोजगार न होने से वहां से पलायन करत है। आपकों बता दें सरकारें गांवों में रोजगार के लिए कई योजनाएं लाती रहती हैं। जिनका मकसद होता है गांवों से शहरों की ओर पलायन रूके।

अभी हाल में महाराष्ट्र में काम करने वाले खासतौर से टैक्सी चलाने वाले गैर मराठियों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई। अब बेचारें हजारों से यूपी, बिहार व उत्तरभारत के लोग कई सालों से वहां काम कर रहे थे उन रोजगार का संकट आ गया है। महाराष्ट्र सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उससे भी ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी उन राज्यों की है जिनके लोग अपने राज्य में रोजगार न होने से वहां से पलायन करत है। आपकों बता दें सरकारें गांवों में रोजगार के लिए कई योजनाएं लाती रहती हैं। जिनका मकसद होता है गांवों से शहरों की ओर पलायन रूके। कांग्रेस की सरकार के समय इसी को देखते हुए मनरेगा शुरू किया गया था। जिसे वर्तमान सरकार ने नामबदल कर बीवीजी-रामजी रख दिया है। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी चालू की गई हैं। पर इनसबके बाद भी जो आंकड़े सामने आते हैं कि पिछले सालों में पलायन रूका नहीं है बल्कि बढ़ा ही है। सरकारों को फिर से अपनी नीतियों की समीक्षा करके कुछ और ठोस व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि ग्रामीण अपने जिले में काम मिल और वह शहरों की ओर न भागे।

घर परिवार चलाने के लिए आजीविका की तलाश सब करते हैं। लेकिन आजीविका की इस तलाश में अपनी माटी से ही नाता टूटने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। कई प्रदेशों में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने का संकट इतना भयावह है कि गांव के गांव खाली होते दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में परिवार यहां से गुजरात और महाराष्ट्र या अन्य विकसीत की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। यह तो तब है कि सरकार ने रोजगार गारंटी को लेकर नियम-कायदे तक बरसों से बना रखे हैं। इन नियमों का फायदा पूरी तरह मिलता दिखे तो भला लोग दूसरे प्रदेशों का रुख क्यों करें? मनरेगा जैसे कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने के लिए ही बनाए गए थे। आदिवासी इलाकों में होली व दिवाली अब सिर्फ त्योहार नहीं रहे, पलायन के कैलेंडर बन चुके हैं। सवाल है कि जब %काम का अधिकार कानून में दर्ज है, तो फिर मजबूरी क्यों? सरकार ने हाल में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (बीवी-जी राम जी) के तहत काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का ऐलान किया। समस्या योजना की मंशा में नहीं, उसके क्रियान्वयन की आत्मा में है। मांग आधारित रोजगार के सिद्धांत को अब बजट आधारित प्रबंधन ने निगल लिया है। होना तो यह चाहिए कि काम तब मिले जब मजदूर मांग करे, लेकिन अब काम तभी मिलता है जब बजट अनुमति दे।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

हिमालय के स्वभाव-सीमाओं को सम्मान से ही सुरक्षा

ओमकार चौधरी

हिमालय केवल बर्फ, पत्थरों और ऊंची चोटियों की पर्वत-श्रृंखला नहीं है। वह दक्षिण एशिया की जल-सुरक्षा, मानसूनी व्यवस्था, जैव-विविधता, कृषि और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। लेकिन जिस हिमालय को हम स्थिर-अडिग मानते आए हैं, वह भू-गर्भीय दृष्टि से दुनिया की सबसे युवा और सक्रिय पर्वत-श्रृंखलाओं में है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने उसकी स्वाभाविक संवेदनशीलता को गंभीर बना दिया है। अब हिमालयी आपदाएं केवल अतिवृष्टि, बादल फटने या भूकंप तक सीमित नहीं हैं। बर्फ, चट्टान, हिमनद झील, नदी, मलबा और मानव निर्मित ढांचे मिलकर ऐसी बहु-आपदा श्रृंखलाएं पैदा कर रहे हैं, जिनका पूर्वानुमान कठिन और विनाश कई गुना हो सकता है। 26 अगस्त, 2026 को नेपाल के रसुवा जिले और तिब्बत-नेपाल सीमा के निकट भोटेकोशी-त्रिशूली नदी क्षेत्र की आपदा इसका नवीनतम उदाहरण है।

वैज्ञानिक आकलन के अनुसार लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद का बड़ा हिस्सा टूटकर करीब 1,200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। बर्फ-चट्टानों के विशाल मलबे ने नदी को अस्थायी रूप से रोका। पानी जमा हुआ और अवरोध टूटते ही जल, मलबे और शिलाखंडों की प्रचंड धारा दौड़ पड़ी। आधे घंटे में नदी का जलस्तर नौ मीटर तक बढ़ गया। जलविद्युत परियोजनाएं, सड़कें, पुल व बस्तियां चपेट में आईं। सबसे चिंताजनक संदेश यह है कि विनाशकारी बाढ़ के लिए निचली घाटियों में भारी वर्षा होना आवश्यक नहीं है। हजारों मीटर ऊपर हिमनद या चट्टान टूट सकती है, नदी अवरुद्ध हो सकती है और प्राकृतिक बांध टूटने पर तुरंत नीचे विनाशकारी बाढ़ पहुंच सकती है। पिछले तीन दशकों की घटनाएं इसी खतरे का संकेत करती हैं। वर्ष 1998 में उत्तराखंड के मालपा में विशाल भूस्खलन ने पूरी बस्ती को नष्ट कर दिया। वर्ष 2000 में तिब्बती क्षेत्र से सतलुज में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई। 2005 में पारिचू नदी पर बने प्राकृतिक अवरोध के टूटने से सतलुज घाटी फिर प्रभावित हुई।

जून, 2013 की केदारनाथ त्रासदी में असाधारण वर्षा, हिम-पिघलाव, चोराबारी ताल से अचानक निकले पानी और विशाल मलबे ने मंदाकिनी घाटी में भयावह विनाश किया। फरवरी, 2021 की चमोली आपदा ने हिमालयी संकट का एक नया रूप सामने रखा। पता चला कि रोंटी क्षेत्र से विशाल चट्टान-हिमस्खलन हुआ था। करीब ढाई

करोड़ घन मीटर चट्टान और बर्फ विनाशकारी मलबा-प्रवाह में बदल गई। ऋषिगंगा-तपोवन जलविद्युत परियोजनाएं चपेट में आईं व 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अक्तूबर, 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक हिमनद झील फटने से तीस्ता में आई बाढ़ ने दिखाया कि ऊंचे हिमालय में उत्पन्न संकट नीचे बांधों-पुलों, शहरों व सामरिक ढांचों को प्रभावित कर सकता है। दरअसल, इन घटनाओं का कारण कहीं अतिवृष्टि, कहीं हिमनद झील, कहीं चट्टान-हिम स्खलन और प्राकृतिक बांध का टूटना है। एक प्राकृतिक संकट दूसरे संकट को जन्म देता है। यही हिमालय की नई बहु-आपदा चुनौती है। दरअसल, भू-गर्भीय संरचना के चलते भारतीय भू-पट्टिका आज भी यूरेशियाई भू-पट्टिका की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोनों के बीच सापेक्ष टकराव करीब 40-50 मिलीमीटर प्रतिवर्ष है। इसी दबाव से हिमालय जन्मा, यही उसे अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र भी बनाता है। हिमालय में तीखी ढलानें, दरारों वाली चट्टानें, पुराने भूस्खलन क्षेत्र और तीव्र कटाव स्वाभाविक हैं। अत: यहां निर्माण व आबादी बढ़ाने से पहले कहीं अधिक सावधानी आवश्यक है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से हिमनद सिकुड़ रहे हैं। फलत: नई झीलें बनी और पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। इसरो ने 1984 से 2023 के उपग्रह चित्रों के आधार पर भारतीय हिमालयी नदी क्षेत्रों में दस हेक्टेयर से बड़ी 2,431 हिमनद झीलों का अध्ययन किया। इनमें 676 झीलों का में विस्तार पाया गया। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में लगभग 200 हिमनद झीलों को खतरनाक माना गया है। दरअसल, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर सकती है।

नदी में पानी के साथ भारी मलबा पहुंचा सकती है। हर हिमालयी आपदा को सड़क, सुरंग या बांध का परिणाम मानना गलत होगा। लेकिन अनियोजित निर्माण प्राकृतिक खतरे को बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल सकता है। सड़कों के लिए पहाड़ काटना, ढलानों पर भारी निर्माण, नदी किनारे होटल और मकान, खराब जल-निकासी, निर्माण का मलबा नदियों में डालना तथा वन क्षेत्र का क्षरण जोखिम बढ़ाते हैं। जोशीमठ इसका उदाहरण है। दरअसल,

स्वास्थ्य अनुसंधान की अनदेखी के चिंताजनक संकेत

दिनेश सी शर्मा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का प्रस्ताव दिया है। यह विभाग करीब दो दशक से मौजूद है, लेकिन अब जाकर इसकी नींद खुली कि भारत में हेल्थ रिसर्च पर कोई खास नीति नहीं है। जुलाई में जारी अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मुख्य संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए रखे फंड का महज 3.3 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को क्रमश: 32 और 15 फीसदी। भारत का आरएंडडी हेतु रखा गया फंड बहुत कम है -जीडीपी का 0.84 फीसदी, जबकि चीन का 2.58 प्रतिशत है। नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के जाहिर लक्ष्यों में से एक बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना है।

लक्ष्य है कि स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश को जीडीपी के अंशानुसार वर्तमान में 0.024 फीसदी से बढ़ाकर 2037 तक 0.072 प्रतिशत और 2047 तक 0.15 फीसदी करना है। भले ही यह बढ़ोतरी बड़ी लग सकती है, लेकिन भारत के मौजूदा और अनुमानित बीमारियों के बोझ और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों की तुलना में यह बहुत कम है। इसके अलावा, प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए समय-सीमा बहुत दूर की है, लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य नहीं व इसके लिए कोई बजटीय मदद भी नहीं है। प्रस्तावित बढ़ोतरी कैसे हासिल की जाएगी, ज़्यादा समस्या वाली बात यह है। नीति में कहा गया है : 'सार्वजनिक निवेश धीरे-धीरे बढ़ेगा, और इसके साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निजी, परोपकारी और गैर-सरकारी निवेश भी होगा'। यह औपचारिक रूप से स्वास्थ्य अनुसंधान में निजी निवेश के लिए द्वार खोलना है। सरकार जिस तरह निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, वह ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए।

नीति में कहा है कि निजी कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक संस्थानों में आरएंडडी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकेगा, और सेहत अनुसंधान विभाग ऐसी फंडिंग को आसान बनाने को ज़रूरी नीतियां बनाएगा। यह तरीका दवा या वैक्सीन विकास के लिए मौजूदा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से अलग है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के विकास जैसी अहम परियोजना के तहत फार्मा कंपनियां और सार्वजनिक संस्थान शामिल होते थे। अगर किसी कंपनी-चाहे वह फार्मा कंपनी हो या कोई और -अथवा किसी कंपनी द्वारा प्रायोजित परोपकारी संस्था से सीएसआर फंड लेने की इजाज़त दी जाएगी, तो इससे अनुसंधान में पक्षपात हो सकता है या कोई छिपा एजेंडा हो सकता है। जैसे कि पर्यावरण से जुड़े सेहत जोखिम (वायु प्रदूषण, तंबाकू, शराब का प्रभाव), पेशेवराना स्वास्थ्य खतरे, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विवादित विषयों पर 'वैज्ञानिक संदेह' निर्मित करना। अजीब बात है कि एक तरफ सरकार ने विदेशी योगदान से जुड़े नियमों के नाम पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कुछ बड़े स्वास्थ्य एनजीओ और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के जमीनी अनुसंधान अध्ययनों की राह में रोड़े अटका दिए तो दूसरी तरफ वह उद्योग जगत और विदेशी संस्थानों द्वारा हेल्थ रिसर्च करने की राह खोल रही है।

जबकि स्वदेशी अनुसंधान करने वालों को अभी भी भारतीय व विदेशी अनुसंधानकर्ताओं के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। ऐसा लगता है कि पूरी सोच स्वास्थ्य अनुसंधान को हर स्तर पर केंद्रीकृत करने और नौकरशाही तंत्र स्थापित करने की है। नीति में एक 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा' बनाने की बात कही गई है जो वृहद स्तर पर प्राथमिकताएं तय करेगा और इस एजेंडा को लागू करने के लिए तीन-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र होगा। सबसे ऊपर 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' होगी जो रणनीतिक दिशा तय करेगी। इसके मुखिया 'प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार' होंगे और इसमें कई नौकरशाह (विज्ञान विभागों के सचिव) सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। दूसरे स्तर पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग होगा, जो मुख्य समन्वय एजेंसी के तौर पर काम करेगा, और तीसरे स्तर पर आईसीएमआर होगा, जिसका जिम्मा वैज्ञानिक एवं तकनीक संबंधी कार्य करना होगा। प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था राज्यों की भूमिका को कमजोर करती है और इस बात को नज़रअंदाज़ करती है कि जनस्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और 'मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान' संविधान की समवर्ती सूची में है।

स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तय करने का अधिकार 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' को देने से राज्य सिर्फ क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएंगे। नीति में कहा गया है, 'राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से काम करने और कार्यक्रम बनाने, बतौर सेवा प्रदाता और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में मदद करेंगे'। नीति एक और अहम बदलाव लाती है- 'एकीकृत स्वास्थ्य' को बढ़ावा देने के नाम पर आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक मेडिसिन के लिए रखे अनुसंधान फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत देना। ऐसा तब हो रहा है जब इन पद्धतियों के लिए आयुष मंत्रालय के तहत अलग से रिसर्च फंड और उसके द्वारा चलाए जा रहे तंत्र मौजूद हैं।

तलवों के दर्द में राहत देंगे ये योगासन

अक्सर देखा गया है हैं कि सुबह उठते ही जैसे ही हम जमीन पर पैर रखते हैं, तलवों में तेज दर्द महसूस होता है? यह समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं या गलत जूते पहनते हैं। वैसे तलवों में दर्द के कई कारण है, जैसे प्लांटर फैसिसाइटिस यानी एड़ी और तलवे में सूजन आने पर, लंबे समय तक खड़े रहने, सख्त सतह पर चलने, गलत जूते पहनने और मोटापा या वजन बढ़ने पर पैरों में दर्द बढ़ जाता है। इस दर्द को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। वैसे अच्छी बात यह है कि कुछ योगासन अपनाकर आप तलवों के इस दर्द से राहत पा सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के।

ताड़ासन

ताड़ासन को समस्थिति भी कहा जाता है। ताड़ शब्द का अर्थ संस्कृत में पर्वत होता है, जिसके ऊपर इस आसन का नाम रखा गया है। ताड़ासन योग का एक मूलभूत आसन है क्योंकि यह आसन अनेक आसनों का आधार है। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनो पंजों को मिलाकर खड़े हो जायें, और बाजुओं को बगल में रखें। शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें। भुजाओं को सिर के उपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा कर हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें। सिर के स्तर से थोड़ा ऊपर दीवार पर एक बिंदु पर आंखें टीका करें रखें। पुर अभ्यास के दौरान आंखें इस बिंदु पर टिका कर रखें। बाजुओं, कंधों और छाती को ऊपर की तरफ खींचें और फैलाएं। पैर की उंगलियों पर आ जायें ताकि दोनो एड़ी उपर उठ जायें। बिना संतुलन और बिना पैरों को हिलायें, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक ताने। श्वास लेते रहें और कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा में ही रहें। ये पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और तलवों में रक्त संचार बढ़ाता है।

वृक्षासन

वृक्षासन (ट्री पोज़) एक प्रसिद्ध योगासन है। शरीर का संतुलन और स्थिरता बेहतर होती है। पैरों, टखनों और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। इस आसन के अभ्यास के लिए एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर रखें। संतुलन बनाए रखें। वृक्षासन का नियमित अभ्यास बैलेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। पैरों के दर्द को कम करता है। जल्दी राहत पाने के लिए सही और आरामदायक जूते पहनें।

पादांगुष्ठासन

योग का एक बुनियादी और महत्वपूर्ण आसन है, जिसका नाम संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है पाद यानी पैर, अंगुष्ठ यानी पैर का अंगूठा, और आसन। इस आसन के अभ्यास के लिए सीधे खड़े हो जाएं। फिर आगे की ओर झुककर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। पादांगुष्ठासन का अभ्यास तलवों और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है। इससे शरीर, खासकर पैरों की अकड़न कम होती है। जल्दी राहत पाने के लिए साथ ही ज्यादा देर खड़े रहने से बचें। इसका अभ्यास करने से टांगों, घुटनों और टखनों में खिचाव लाता है और उन्हे मज़बूत बनाता है। जिस टांग को आप उठाते हैं, उस टाँग की हॅम्स्ट्रिंग और कूल्हे में ख़ास तौर से अच्छा खचाव लाता है। जिस टाँग पर आप खड़े होते हैं, उसको यह ख़ास तौर से मज़बूत बनाता है। ध्यान रखने की क्षमता में सुधार लाता है। आपके शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है।

अधो मुख श्वानासन

अधो मुख श्वानासन का नाम तीन शब्दों के मेल से रखा गया है अधः मुख और श्वान। अधस् का मतलब नीचे की ओर गया हुआ, मुख यानी मूह, और श्वान का अर्थ है कुत्ता। अधो मुख श्वानासन सूर्य नमस्कार ए और सूर्य नमस्कार बी का एक स्टेप है। ये योगासन शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को लंबा करता है, और मन को शांत करता है। इस आसन के अभ्यास से एड़ी और तलवे में खिंचाव आता है। एड़ियों के दर्द में तुरंत राहत मिलती है। अधोमुख श्वानासन के अभ्यास के लिए जमीन पर घुटनों और हाथों के बल आएं (मेज की स्थिति)। सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीधा करें और अपने कूल्हों (हिप्स) को ऊपर उठाएं। शरीर से उल्टा वी आकार बनाएं। हाथों को जमीन पर मजबूती से दबाएं और सिर को कंधों के बीच रखें। प्रमुख लाभ बाजू और टांगें मजबूत होती हैं। कंधे और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है।सिरदर्द और थकान से राहत मिलती है। जल्दी राहत पाने के लिए गर्म पानी से पैर सेंकें।

मालासन

मालासन जिसे गारलैंड पोज या योगिक स्क्वाट के नाम से भी जाना जाता है। मालासन या माला आसन एक बैठने वाला आसन है जो पाचन तंत्र, पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों को लाभ पहुंचाता है। इस मुद्रा का नाम संस्कृत के शब्द 'माला' से आया है, जिसका अर्थ है माला, और 'आसन', जिसका अर्थ है योग मुद्रा। मालासन के अभ्यास के लिए स्काट पोजिशन में बैठें और हाथ जोड़ें। इस आसन के अभ्यास के कई फायदे हैं। इससे पैरों की फ्लैक्सिबिटी बढ़ती है और दर्द व सूजन से राहत मिल सकती है। जल्दी राहत पाने के लिए योग के अलावा सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करें।

हंसना मना है

आज कुछ घबराये से लगते हो, ठंड में कपकपाये से लगते हो, निखर कर आई है सुरत आपकी, बहुत दिनों बाद नहाये से लगते हो।

बेटा: पापा आप शराब मत पिया करो। पापा: पिने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है? बेटा: आप इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे?

पप्पू (अपनी मां से)- मां, मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूं? मां- पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़...!

पापा और 15 साल का बेटा एक होटल में गए, पापा: वेटर एक बियर और एक आईसक्रीम लाओ, बेटा: आईसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिये ना, दे.. चप्पल.. पे.. चप्पल!

हंसी के लिए गम कुर्बान, खुशी के लिए आंसू कुर्बान, दोस्त के लिए जान भी कुर्बान, और, अगर दोस्त की गर्लफ्रेंड मिल जाये तो, दोस्त भी कुर्बान।

एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी, दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी, तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि, लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं...

कहानी | कौवा और कोयल

चांदनगर के पास एक जंगल में बड़ा-सा बरगद का पेड़ था, जिसपर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने-अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते-ही-देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा कि हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्यों न जब मैं अंडा दूं, तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना और जब तुम अंडा दोगे, तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी? कौवे ने कोयल की बात पर सहमती जताई। संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा कि तुम्हारी चोंच साफ नहीं है। तुम इसे धोकर आओ। फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो। मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी बोली पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा कि मुझे घड़ा दे दो। कुम्हार ने कहा कि तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूं। यह सुनते ही कौवा, धरती मां से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला, मां मुझे मिट्टी दे दो। धरती मां बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी। उसी से खोदकर मिट्टी निकलेगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो। लोहार ने गर्म-गर्म खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए।

7 अंतर खोजें

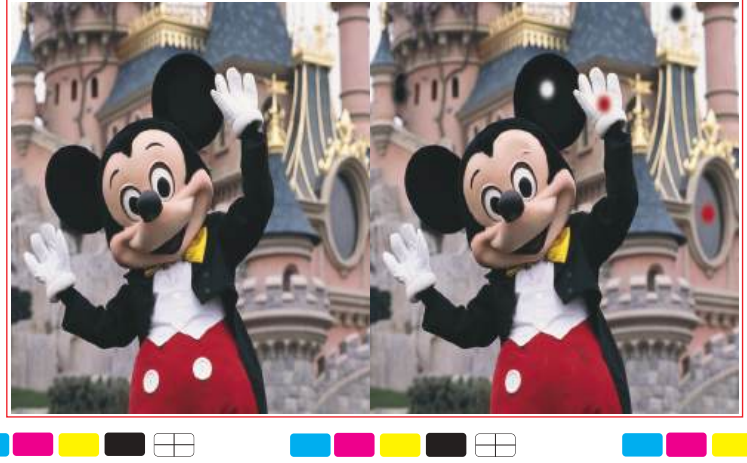

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके निर्णय सटीक साबित होंगे। कारोबारी हैं तो व्यापारिक मुनाफे में वृद्धि होगी। निवेश के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृषभ कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें। कारोबार में उधारी के लेनदेन से बचें। जोखिमभरे सौदों को टालना बेहतर रहेगा।

मिथुन कार्यस्थल पर बौद्धिक क्षमता के बल पर जटिल समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। कारोबारी हैं तो नेटवर्किंग से व्यापार में विस्तार होगा। नए अनुबंध मिल सकते हैं।

कर्क कार्यस्थल पर मन को एकाग्र रखें। दफ़्तर में किसी भी गुटबाजी से दूर रहें। साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं तो पारदर्शिता जरूर बनाए रखें। लेनदेन में सतर्कता बरतें।

सिंह नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास कार्यक्षेत्र में आगे रखेगा। प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। कारोबार में नए ग्राहकों से जुड़ाव होगा, बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है।

कन्या अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें, कागजी काम में गलती से बचें। सफलता मिलेगी। कारोबार में प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर नजर रखें। नए सौदे संभलकर करें।

तुला कार्यस्थल पर रचनात्मक सोच से कार्यशैली में निखार आएगा। कठिन लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे। शेयर बाजार व कमोडिटी से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ की संभावना है।

वृश्चिक कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और एकाग्रता से आगे बढ़ें। रियल एस्टेट या निर्माण कार्य से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा। पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

धनु करियर में उन्नति के लिए नए विचार और संपर्क मददगार साबित होंगे। कारोबारी हैं तो छोटी यात्राएं व्यवसाय के दृष्टिकोण से फलदायी रहेंगी।

मकर कार्यस्थल पर दृढ़ निश्चय से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। सफलता मिलेगी। कारोबार में अटकी हुई व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है।

कुम्भ कार्यस्थल पर अलग पहचान बनेगी और प्रभाव बढ़ेगा। अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। नए वेंचर या बिजनेस प्लान शुरू करने के लिए अनुकूल समय है।

मीन दफ़्तर में काम का दबाव अधिक रह सकता है अनुभवी लोगों से सलाह लें। कारोबारी हैं तो विदेशी व्यापार या दूर के सौदों में संभलकर कदम उठाएं। विवाद से बचें।

फिर गूंजेगी आशा भोसले की आवाज

महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका इस साल 12 अप्रैल को निधन हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर उनकी आवाज उनके फैंस तक पहुंचने वाली है। उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है। आशा भोसले के आखिरी रिकॉर्ड किए गए गाने को उनकी जयंती के खास मौके पर रिलीज किया जाएगा। यह गाना फिल्म 'ओम का हरी' का हिस्सा है और 8 सितंबर को रिलीज होगा। गाने का नाम 'ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां' है। खास बात यह है कि आशा भोसले ने इस गाने को साल 2023 के आखिर में रिकॉर्ड किया था।

फिल्म के मेकर्स ने आशा भोसले की लंबी और शानदार संगीत यात्रा को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पर

यह गाना रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म के डायरेक्टर हरीश व्यास ने कहा कि आशा जी के जन्मदिन पर गाना रिलीज करना उनकी सदाबहार आवाज और उनकी शानदार विरासत का जश्न मनाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले के संगीत ने कई पीढ़ियों के लोगों की जिंदगी को छुआ है।

'ओम का हरी' एक ड्रामा-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन हरीश व्यास ने किया है। फिल्म में अंशुमान झा, रघुबीर यादव, सोनी राजदान और आयशा कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक पिता और बेटे के रिश्ते के आसपास घूमती है। इसमें दो पीढ़ियों के बीच के फर्क, परिवार और प्यार को दिखाया गया है। साथ ही कहानी उन भावनाओं की भी बात करती है, जिन्हें कई बार अपने करीबी लोगों से कह नहीं पाते।

आशा भोसले का गाना भी फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा है और इसमें खुशी, प्यार और अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की बात की गई है। आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था।

28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी आलिया भट्ट की 'अल्फा'

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब दर्शक इस एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर को घर बैठे देख सकेंगे। यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-केंद्रित फिल्म है, जिसमें आलिया और शरवरी पहली बार साथ नजर आई हैं।

'अल्फा' 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में दोनों एक्ट्रेस स्पाई का किरदार निभाती हैं और एक खतरनाक मिशन का हिस्सा बनती हैं। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा और इसे कहानी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। नेटफ्लिक्स ने 27 अगस्त को फिल्म की OTT रिलीज का ऐलान किया।

'अल्फा' 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'अल्फा गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए।

फिल्म की कहानी YRF स्पाई यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इसमें आलिया भट्ट R&AW एजेंट सीता के किरदार में हैं। सीता एक बेहद काबिल एजेंट है, जिसे आगे चलकर अल्फा सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं शरवरी फिल्म में दुर्गा कौल का किरदार निभा रही हैं, जो सीता की अलग रह रही जुड़वां बहन है। दोनों की जिंदगी एक खतरनाक मिशन के दौरान आपस में जुड़ती है।

फिल्म में बॉबी देओल विलेन कर्नल फतेह सिंह लखावत के रोल में नजर आते हैं। उसका एक शक्तिशाली सीरम 'अल्फा' से जुड़ा प्रयोग कहानी को आगे बढ़ाता है। सीता का अपहरण कर उसे अपने नियंत्रण में रखा जाता है और धीरे-धीरे उसे एक सुपर-सोल्जर में बदल दिया जाता है। फिल्म में अनिल कपूर भी अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन के 'वॉर' वाले किरदार कबीर का भी कैमियो देखने को मिलता है। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, ऐसे में जिन दर्शकों ने इसे थिएटर में नहीं देखा, उनके पास इसे घर बैठे देखने का मौका है।

बॉलीवुड | मन की बात

मैं लिखती कुछ हूं, शूट कुछ और करती हूं : गीतू मोहनदास

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक-ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यश के फैंस को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म लोगों को प्रभावित करने में विफल रही। यश ने गीतू के साथ मिलकर को कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। अब इंटरनेट पर गीतू का साल 2021 का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वह फिल्म के बारे में बात कर रही हैं और फिल्म की आलोचना का कारण अपनी लेखन प्रक्रिया को बता रही हैं। फिल्म कमपैनियन को दिए इंटरव्यू में गीता को कहते हुए सुना जा सकता है, मैं लिखती कुछ हूं, कुछ और शूट करती हूं और एडिट कुछ करती हूं, और फिर फिल्म रिलीज हो जाती है। तब मैं खुश हो जाती हूं। मैं कभी भी स्क्रिप्ट पर टिकी नहीं रहती। यहां तक कि शूटिंग के दौरान भी, जैसे कि अभी अपनी अगली फिल्म के लिए, मैं प्रोड्यूसर्स वगैरह से मिलती रहती हूं, तो जब मैं उनसे बात करती हूं, तो मैं उन्हें बस यही एक बात कहती रहती हूं कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पढ़ रहे हैं। इस क्लिप को शेयर करते हुए एक यूज़र ने लिखा, टॉक्सिक की शूटिंग शुरू होने से पहले गीतू मोहनदास का इंटरव्यू, मैं कुछ और लिखती हूं, कुछ और शूट करती हूं, कुछ और एडिट करती हूं। फिर फिल्म रिलीज होती है। तब मैं खुश होती हूं। मैं कभी भी स्क्रिप्ट पर टिकी नहीं रहती। जब मैं अपनी अगली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स से मिलती हूं, तो मैं उनसे भी यही कहती हूं,आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पढ़ रहे हैं। अब इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। एक ने लिखा, शायद इसी वजह से To&ic को इतनी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। दूसरे ने आगे कहा, इसलिए फिल्म में ये सब पुराना लग रहा है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के लिए आपके पास स्पष्टता या दूरदृष्टि नहीं है। आपकी दूरदृष्टि की कमी स्क्रीन पर साफ दिख रही है। और आप इसका दिखावा कर रहे हैं? वाह!

ये है दुनिया का असली केला! घने जंगलों में ही होते हैं पैदा, बाजार में बिकता है हाइब्रिड नस्ल

केला दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। भारत हो या कोई और देश, लगभग हर घर में केला खाया जाता है। नाश्ते में, दूध के साथ, शेक में या सीधे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो केला आप रोज खा रहे हैं वो असल में असली केला नहीं है? जी हां, बाजार में बिकने वाला केला हाइब्रिड नस्ल का है जिसमें बीज नहीं होते। असली केला घने जंगलों में पैदा होता है और उसमें सख्त बीज भरे होते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों असली केले की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग घने जंगलों में जाकर जंगली केले तो? रहे हैं और उसका स्वाद चखने का दावा कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि असली केले का आकार आम केले से अलग होता है और काटने पर अंदर काले-काले सख्त बीज नजर आते हैं। खाने वाले कह रहे हैं कि स्वाद भी अलग है। थोड़ा खट्टा, पल्प कम और बीज ज्यादा। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आज दुनिया भर में खाया जाने वाला केला मुख्य रूप से कैवेंडिश किस्म का है। ये एक हाइब्रिड यानी संकर प्रजाति है जो दो जंगली प्रजातियों- म्यूसा एक्यूमिनाटा और म्यूसा बाल्बिसियाना के मिश्रण से विकसित हुई है। इसमें बीज नहीं बनते क्योंकि ये पार्थेनोकार्पी प्रक्रिया से फल देता है। यानी बिना परागण के ही फल बन जाता है। इसी वजह से बाजार का केला खाने में आसान और सुविधाजनक है। लेकिन असली या जंगली केला पूरी तरह अलग होता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के कुछ घने वर्षा वनों में प्राकृतिक रूप से उगता है। जंगली केले में बड़े-बड़े कठोर बीज होते हैं जो लगभग पूरे फल में फैले रहते हैं। पल्प बहुत कम होता है और बीज इतने सख्त होते हैं कि उन्हें कुतरना पड़ता है। स्वाद भी मीठा कम और थोड़ा कसैला या खट्टा ज्यादा होता है। स्थानीय आदिवासी और जंगल में रहने वाले समुदाय इन जंगली केलों को पीढ़ियों से जानते और खाते आए हैं। वे इन्हें पकने पर तोड़ते हैं, बीज निकालकर या कुतरकर खाते हैं। कुछ जगहों पर इसे औषधीय गुणों वाला भी माना जाता है। लेकिन आम बाजार में ये केला इसलिए नहीं बिकता क्योंकि बीज होने की वजह से खाने में असुविधा होती है और व्यावसायिक उत्पादन मुश्किल है।

अजब-गजब | ये है दुनिया का अनोखा आइलैंड

यहां इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं केकड़े

आमतौर पर अगर सड़क पर एक-दो केकड़े भी चलते हुए दिख जाएं तो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सड़क पर एक साथ हजारों-लाखों केकड़े नजर आने लगें और दूर तक सिर्फ लाल रंग ही दिखाई दे, तो नजारा कैसा होगा? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ऐसा द्वीप है, जहां साल के एक खास समय में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। यहां सड़कें, जंगल और घरों के आसपास की जगहें लाल केकड़ों से भर जाती हैं। यह अनोखा नजारा क्रिसमस आइलैंड पर देखने को मिलता है।

हर साल प्रजनन के मौसम में करोड़ों लाल केकड़े अपने प्राकृतिक आवास से समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। उस समय पूरा द्वीप जैसे केकड़ों की एक लंबी यात्रा का गवाह बन जाता है। क्रिसमस आइलैंड पर लाल केकड़ों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन साल के एक खास समय में इनकी संख्या देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जंगल से निकलकर ये केकड़े सड़कों और इंसानी बस्तियों के बीच से गुजरते हुए समुद्र की ओर बढ़ते हैं। इनके झुंड इतने बड़े होते हैं कि कई जगहों पर जमीन का रंग ही लाल दिखाई देने लगता है। सड़कें हों, घरों के आसपास का इलाका हो, रेस्टोरेंट हों या बस स्टॉप, कई जगहों पर केकड़े चलते हुए नजर आ सकते हैं। इस दौरान ऐसा लगता है मानो पूरा द्वीप इन जीवों से भर गया हो। हर साल लगभग नवंबर से जनवरी के बीच लाल केकड़ों का यह सफर शुरू होता है। बारिश और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के साथ ये केकड़े

जंगल से निकलकर समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। उनका मकसद समुद्र तक पहुंचकर प्रजनन करना होता है। इस दौरान लाखों-करोड़ों केकड़े एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं। यही वजह है कि क्रिसमस आइलैंड का यह नजारा दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता है।

इतनी बड़ी संख्या में केकड़ों के सड़क पर आने की वजह से लोगों के लिए वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इनके प्रवास के दौरान कई सड़कों को बंद कर दिया जाता है या वहां वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। जहां सड़कें पूरी तरह बंद नहीं होतीं, वहां लोगों को बेहद धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। जगह-जगह चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि सड़क पार करते समय केकड़ों को नुकसान न पहुंचे। इसके बावजूद कई केकड़े वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए इनके सुरक्षित सफर के लिए प्रशासन की ओर से अलग-अलग इंतजाम किए जाते हैं। कई जगहों पर केकड़ों को सड़क पार कराने के लिए खास रास्ते भी बनाए गए हैं। क्रिसमस आइलैंड लगभग 52 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां की आबादी करीब 2,000 लोगों की है। इतनी कम आबादी वाले इस द्वीप की पहचान वहां रहने वाले लाल केकड़ों की वजह से दुनिया भर में बनी हुई है। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इस अनोखी प्राकृतिक घटना को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लाल केकड़ों को जंगल से समुद्र की ओर जाते देखना लोगों के लिए बेहद खास अनुभव होता है।

क्रिसमस आइलैंड लाल केकड़ों के लिए बेहद अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है। घने जंगल और समुद्र के करीब होने की वजह से यहां इन केकड़ों को रहने और प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। यही कारण है कि लाल केकड़ों की इतनी बड़ी आबादी इस द्वीप पर पाई जाती है। हर साल उनका समुद्र की ओर जाना यहां की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ समय के लिए पूरा द्वीप लाल केकड़ों से ढक जाता है और फिर धीरे-धीरे ये वापस जंगल की ओर लौट जाते हैं। इसलिए क्रिसमस आइलैंड का यह नजारा सिर्फ देखने में अजीब नहीं, बल्कि प्रकृति के एक बेहद खास चक्र की कहानी भी बताता है। जहां आम जगहों पर सड़क पर एक केकड़ा दिखना भी असामान्य लग सकता है, वहीं इस द्वीप पर हर साल लाखों-करोड़ों लाल केकड़ों का एक साथ सफर करना यहां की पहचान बन चुका है।

बस फ्री पर सफर गायब, रक्षाबंधन पर योगी का ये है तोहफा

» महिलाओं का आरोप बसें रुकी ही नहीं,

» सड़क किनारे इंतजार करती रह गईं बहनें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बस फ्री थी लेकिन बस ही नहीं आई। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया तो सरकार ने इसे बहनों के लिए बड़ा तोहफा बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो अब इस दावे की चमक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं महिलाएं बस के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी हैं कहीं हाथ देकर बस रोकने की कोशिश कर रही हैं और कहीं उनका आरोप है कि बस चालक ने बस रोकी ही नहीं। यानी सरकारी ऐलान कागज पर मुफ्त सफर का था लेकिन सड़क पर सवाल यह खड़ा हो गया कि जब बस ही नहीं रुकेगी तो मुफ्त यात्रा आखिर होगी कैसे?

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई पहली पहल नहीं है। पिछली सरकारों के दौर में भी त्योहारों पर महिलाओं को ऐसी सुविधाएं दी जाती रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज शिकायत दर्ज कराने के लिए अखबार के अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। मोबाइल कैमरा ऑन होता है, वीडियो बनता है और कुछ ही मिनटों में सरकार की घोषणा और जमीन की हकीकत आमने-सामने खड़ी हो जाती है।

अतिरिक्त बसों की पर्याप्त व्यवस्था पर भी सवाल

और यही वह जगह है जहां सरकार से सवाल बनता है। क्या परिवहन विभाग ने रक्षाबंधन के लिए अतिरिक्त बसों की पर्याप्त व्यवस्था की थी? क्या चालक-परिचालकों को महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के साथ उन्हें प्राथमिकता से बस में बैठाने के निर्देश दिए गए थे? क्या प्रमुख रूटों और बस स्टॉप पर निगरानी की व्यवस्था थी? और अगर सोशल मीडिया पर इतनी महिलाओं ने अपनी परेशानी दर्ज कराई है तो परिवहन विभाग ने इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की? सरकार कह सकती है कि लाखों महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। यह आंकड़ा अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में एक महिला की शिकायत भी सुनना जरूरी है। क्योंकि योजना का आंकड़ा सरकार बताती है, लेकिन उसकी असली कहानी सड़क बताती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें हैं वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई महिलाओं की शिकायत यही है कि वे बस स्टॉप या सड़क किनारे खड़ी रहीं, लेकिन बसें नहीं रुकीं। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने हाथ देकर बस रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके बस आगे निकल गई। इस तरह की शिकायतों की मौजूदगी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या मुफ्त यात्रा की घोषणा के साथ सरकार ने बसों को महिलाओं को बैठाने की स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की थी? क्योंकि सरकारी योजना की सफलता सिर्फ घोषणा से तय नहीं होती। सफलता तब मानी जाती है जब जिस महिला के लिए सुविधा घोषित हुई है, वह वास्तव में उसका लाभ उठा सके। अगर सड़क पर खड़ी महिला बस को हाथ देती रहे और बस उसकी आंखों के सामने निकल जाए तो उसके लिए सरकारी घोषणा और मुफ्त यात्रा में जमीन-आसमान का अंतर रह जाता है। रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का त्योहार है। सरकार ने इसे महिलाओं के लिए सुविधा देने का अवसर बनाया, अच्छी बात है। लेकिन बहनों को सिर्फ घोषणा नहीं चाहिए–बस चाहिए, जो रुके भी। अब सवाल सीधा है–योगी सरकार ने बस यात्रा तो मुफ्त कर दी, क्या महिलाओं तक बस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पूरी की? बस फ्री थी, लेकिन अगर बस रुकी ही नहीं तो फिर यह सुविधा किसके लिए थी?

सोनिया गांधी की किताब छापने से क्यों रोका जा रहा : अशोक गहलोत

» बोले- कौन डाल रह है दबाव, यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या के समान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब को भारत में प्रकाशित होने से दबाव डालकर रोका जा रहा है। गहलोत ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या के समान है। गहलोत ने कहा कि सोनिया का जीवन त्याग और बलिदान की मिसाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक बयान में कहा, सोनिया की आने वाली किताब को पेंगुइन वर्ल्डवाइड कंपनी मूलस्वरूप में दुनियाभर में छापने को तैयार है पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया भारत में इसे लॉन्च करने के लिए बदलाव करवाना चाहता है। गहलोत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर ऐसी कौन-सी वजह या कौन सा दबाव है जो दुनिया-भर में छापा जा रहा है उसे भारत में नहीं छाप सकते।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इसके लिए प्रकाशक पर दबाव डाला गया है। उन्होंने कहा, असली मुद्दा यह है कि पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया कि मोदी, आरएसएस और चीन द्वारा मोदी राज में भारतीय भूभाग पर कब्जे से जुड़े हिस्से हटाए जाएं। यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा, इस सच को आखिर भारत की जनता के सामने आने से क्यों छिपाया जा रहा है? क्या मोदी सरकार प्रकाशकों पर दबाव डालकर तथ्यों को भी बदलवा देगी?

कैबिनेट से हटाने की साजिश हो रही, अब 2029 चुनाव लड़ूंगा: जुएल ओराम

» केंद्रीय मंत्री अपनी पार्टी व सहयोगियों पर बरसे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने अपनी ही पार्टी के सहयोगियों पर कैबिनेट से हटाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस अभियान को सहयोगी राकेश पासवान की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि वे साजिशकर्ताओं के हाथ काटने की क्षमता रखते हैं। ओराम ने कहा कि इन राजनीतिक हालात के कारण उन्होंने 29 का चुनाव न लड़ने का अपना फैसला अब बदल दिया है, जिससे ओडिशा बीजेपी में हलचल मच गई है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और बीजेपी नेता जुएल ओराम ने अपनी ही पार्टी के कुछ सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे उनकी छवि खराब करने और उन्हें कैबिनेट से बाहर करने के लिए उनके खिलाफ़ अभियान चला रहे हैं।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इसमें शामिल लोगों के हाथ काटने की ताकत उनमें है। यह बयान तब आया जब उनके एक सहयोगी, राकेश पासवान को ओडिशा के राउरकेला में एक संगठित अपराध के मामले से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पासवान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओराम ने पहले कहा था कि उन्हें पासवान के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है। पासवान को स्टील सिटी में सरकारी गेस्ट हाउस में अपराधियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। पत्रकारों से बात करते हुए ओराम ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता उनकी छवि खराब करने और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटवाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, ताकि वे मंत्री के तौर पर उनकी जगह ले सकें। उन्होंने कहा कि हाल ही में, कुछ लोग मुझे बदनाम करने और मेरी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं।

नेकां में 370 की बहाली के मुद्दे पर बवाल

» रूहुल्ला 3 नवंबर को छोड़ेंगे संसद और पार्टी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में सियासी बवाल मच गया है। पार्टी के रुख से खफा श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी पार्टी छोड़ेंगे। नेकां अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की खुली चुनौती को सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए रूहुल्ला ने ऐलान किया है कि वह तीन नवंबर को संसद और पार्टी दोनों छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पार्टी के बदलते रुख को लेकर नेतृत्व से जवाब मांगा है। कहा- मैं झूठ और फरेब का हिस्सा नहीं बन सकता। रूहुल्ला ने तुरंत इस्तीफा न देने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा, औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंपने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं।

मुझे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड बांटना है। मैंने जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए लड़ने की अपनी कोशिशों के तहत श्रीनगर में एक सम्मेलन की योजना बनाई है। इसमें देश के कुछ सांसदों को आमंत्रित किया गया है। रूहुल्ला के लिए तीन नवंबर का दिन अहम है। इसदिन उनके पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं बरसी है। आगा मेहदी की आतंकियों ने आईईडी विस्फोट में हत्या कर दी थी। रूहुल्ला इस दिन अपने गढ़ बडगाम में एक बड़ी जनसभा करने की योजना बना रहे हैं। जनसभा में वे इस्तीफा पत्र जारी करेंगे और सांसद पद छोड़ने के कारण बताएंगे।

उमर ने छोड़ दी है पार्टी की विचारधारा : रूहुल्ला

रूहुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पार्टी की विचारधारा छोड़ने और खत्म किए गए आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य दर्जे की बहाली के लिए लड़ने के अपने वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि हम झूठ और धोखे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस्तीफा देने के बाद रूहुल्ला की योजना सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करने और श्रीनगर सीट से ही उपचुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा, एक बार उपचुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मैं लोगों से सलाह-मशविरा करूंगा और हो सकता है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव लड़ूं।

नेपाल में अब तक 626 लोगों की मौत

2400 से ज्यादा लापता, सरकार ने जारी किए आंकड़े, राहत-बचाव अभियान जारी

काठमांडू। नेपाल के दक्षिणी मध्य तराई क्षेत्र के चितवन जिले के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से अब तक बरामद किए गए 233 शवों में से केवल चार की ही पहचान हो पाई है। चितवन जिला प्रशासन कार्यालय ने एक बयान में कहा, स्वास्थ्य संस्थानों और नदी तटों से एकत्र किए गए शव/अवशेष सड़ने की अवस्था में हैं और अब उनकी पहचान करना संभव नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि शेष 229 शवों को हिरासत केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में रखा जा रहा है, और डीएनए के नमूने अभी भी एकत्र किए जा रहे हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। नेपाल बाढ़ त्रासदी में अब तक 626 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक लापता लोगों की संख्या 2426 है।

जापान में सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है बीसीसीआई

» एशियाई खेलों में बी टीम भेजने पर कर रहा विचार टीम में होगा बदलाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) जापान में सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है। इस कारण बीसीसीआई एशियाई खेलों के लिए भारत की बी टीम भेजने पर विचार कर रहा है। एशियाई खेलों में पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से तीन अक्तूबर तक, जबकि महिलाओं का टूर्नामेंट 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आयोजित किया जाना है। बीसीसीआई ने बताया कि बोर्ड और एसीसी जापान में क्रिकेटरों के लिए की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं से खुश नहीं हैं और बोर्ड वहां एक पर्यवेक्षक भेजने पर विचार कर रहा है।

यदि सुविधाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं पाई जाती हैं, तो बीसीसीआई प्रतियोगिता के लिए बी टीम भेजने पर विचार कर सकता है। बीसीसीआई भेजे गये पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में यदि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुईं, तो हम वहां बी टीम भेजने पर विचार कर सकते हैं। हमने एसीसी की एक बैठक के दौरान जापान ओलंपिक अधिकारियों से कहा था कि ड्रेसिंग रूम टेंट में बनाए गए हैं और उन टेंटों से शौचालय 500 मीटर की दूरी पर हैं, जिससे खिलाड़ियों के लिए असंतोषजनक स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा, होटल के कमरे वाकई बहुत छोटे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर, बाएं हाथ के बल्लेबाजों की तिकड़ी अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा तथा स्टार तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह सहित एक मजबूत लाइन-अप का एलान किया था। भारतीय महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है और इसमें कई ऐसे बड़े नाम शामिल हैं जो सीनियर स्तर पर नियमित रूप से खेलते हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बीसीसीआई आकिब को काउंटी क्रिकेट खिलाने की तैयारी

नईदिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का मौका दिलाने की कोशिश कर रहा है। बीसीसीआई कुछ इंग्लिश काउंटी क्लबों के संपर्क में है, ताकि नबी को काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम दौर में 2-3 रेड-बॉल मुकाबले खेलने का मौका मिल सके। आकिब नबी ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 विकेट हासिल किए थे और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। हालांकि, हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी। भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति की योजना है कि तेज गेंदबाजों को पर्याप्त रेड-बॉल क्रिकेट मिले। इसी वजह से आकिब नबी के लिए इंग्लैंड में कुछ काउंटी मैचों की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है।

बहुत झेल लिया नफरत का जहर अब मोहब्बत की सरकार बनाएंगे

क्षितिजकांत

बेबाक बोल जनता खोल रही पोल

सहारनपुर सिटी विस की ग्राउंड रिपोर्ट

» सहारनपुर सिटी में एनडीए के खिलाफ मुस्लिम समाज लामबंद

» सहारनपुर सिटी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

सहारनपुर। सहारनपुर सिटी विधानसभा में इस बार सियासी पारा चढ़ गया है। गुज्जर और तेली बिरादरी ने एक सुर में एनडीए सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है और इंडिया गठबंधन को खुला समर्थन दे दिया है।

सहारनपुर सिटी विधानसभा में 27 की सियासी बिसात बिछने लगी है। पसमांदा समाज ने नफरत की सियासत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

2027 विनस चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी

तेली समाज से आने वाले हाजी इसरार ने हुंकार भरते हुए कहा - 2027 विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी। नफरत की सरकार को हटाने के लिए हम तमाम पसमांदा और सेक्युलर लोग एकजुट होकर वोट करेंगे। आंकड़ों के साथ सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा - सहारनपुर में 50 प्रतिशत मुस्लिम वोटर है, जिसमें 92प्रतिशत पसमांदा वोटर है। अकेले तेली समाज के ही 75,000 वोटर हैं। इमरान मसूद को लेकर उन्होंने बड़ा सियासी बम फोड़ा - अगर इमरान मसूद सहारनपुर की कमान संभालते हैं तो 7 में से 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा।

गुज्जर समाज का ऐलान- भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे

गुज्जर समाज से मोहम्मद असगर ने कहा - हम खुलकर कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा को हम कभी वोट नहीं देंगे। जब से भाजपा सरकार आई है, मोहब्बत और प्यार खत्म हो गया है। आपसी प्रेम और सौहार्द खत्म हो गया है। जगह-जगह हिंदू-मुस्लिम के बीच नफरत दिखाई देती है, जब यह सरकार नहीं थी तो आपसी भाईचारा था।

'एनडीए मुसलमानों पर अत्याचार करती है'

तेली बिरादरी के मोहम्मद तहसीन मलिक ने कहा हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। एनडीए मुसलमानों के साथ अत्याचार करती है, इसलिए हम एनडीए को वोट नहीं करेंगे। मॉब लिंचिंग हो रही है, मदरसे गिराए जा रहे हैं, कई मस्जिदें गिराई जा रही हैं। मुस्लिम की तो एकदम खिलाफत हो रही है।

शाहनवाज मलिक बोले- हर समाज बदलाव चाहता है

तेली बिरादरी के ही शाहनवाज मलिक ने सरकार बदलने का ऐलान किया - हम सरकार का बदलाव चाहते हैं, हमें हर सूरत में इस सरकार का बदलाव करना ही है। मुसलमान ही नहीं, हर समाज का व्यक्ति इस सरकार से परेशान है। इमरान मसूद को हर समाज पसंद करता है, जैसे वह स्वीक बने वैसे ही इंडिया गठबंधन का विधायक भी बनेगा।

ओवैसी का एक वोटर नहीं, बाटोगे तो काटोगे, नफरती नारा

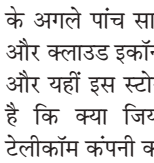

तेली बिरादरी के सीनियर नेता हाजी मोहम्मद इस्लाम ने सबसे आक्रामक बयान दिया - हम 5 साल से हर समय तैयारी में हैं कि किस तरह ये सरकार हटे। असदुद्दीन ओवैसी का एक भी वोटर सहारनपुर में नहीं है। मुसलमान का वोट सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। उन्होंने कहा - इंडिया गठबंधन नफरत की राजनीति नहीं करता। हमारा नेता अखिलेश यादव है, हम उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी हर समय सड़क पर हैं, पब्लिक और नौजवानों के मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए हाजी ने कहा - बाटोगे तो काटोगे ये नफरती नारा है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चाहते हैं। इन नफरतियों को हिंदुस्तानियों ने सिरे से नकार दिया है। बहुत दिन तक जनता को बरगलाया है, अब समझ आ गया है कि हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जिसमें हिंदू-मुस्लिम एक जगह बैठकर खाएं और आपसी भाईचारा बना रहे।

निर्वाचन क्षेत्र क्रम-1

सहारनपुर नगर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 है। सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र 1955 में अंतिम आदेश डीसी (1953-1955) के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। इस निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और क्रम संख्या को अंतिम बार संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में परिभाषित किया गया था।

राजनीतिक स्थिति और विधायक

2022 का चुनाव- 22 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव गुंबर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय गर्ग को हराया था। 2017 का चुनाव:-र्ष 2017 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के संजय गुंबर/संजय गर्ग ने जीत दर्ज की थी।

चुनावी समीकरण

यहाँ मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मतदाता चुनावी नतीजों को तय करते हैं। समय-समय पर यहाँ के राजनीतिक दलों और विधायकों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे यह सीट और अधिक चर्चा में रहती है।

नामकरण और स्थापना

परंपरा के अनुसार, इस नगर की स्थापना राजा सह रणवीर सिंह (सहारनवीर) ने की थी, जिन्हें यहाँ की जागीर दी गई थी। सूफी संत शाह हारून, शहर का नाम प्रसिद्ध सूफी संत संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर भी रखा गया माना जाता है। अकबर के शासनकाल में इसका नाम शाहारूनपुर से बदलकर सहारनपुर कर दिया गया।

ऐतिहासिक कालक्रम

दिल्ली सल्तनत: 13वीं शताब्दी (लगभग 1211 ईस्वी) के आसपास यह क्षेत्र दलदली और वीरान था, जो बाद में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के अधीन आया। 1325 में यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का प्रभाव रहा और 1398 में तैमूर लंग ने भी यहाँ आक्रमण किया था। **मुगल काल :** अकबर के शासनकाल में इस क्षेत्र का प्रशासनिक और राजस्व संगठन हुआ। बाद में शाहजहाँ ने यहाँ बादशाही बाग और बादशाही महल जैसे शिकारगाहों का निर्माण कराया। **मराठा शासन:** 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में (1757 के बाद) यह शहर मराठों के नियंत्रण में आया और 1789 में मराठा राज्य का उत्तरी जिला बना। **ब्रिटिश काल :** वर्ष 1803-1804 में मराठा प्रतिरोध और सिख आक्रमणों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया।

सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान

लकड़ी की नक्काशी: सहारनपुर को भारत की वुड क्राफ्ट कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की लकड़ी की नक्काशी देश-विदेश में प्रसिद्ध है। **धार्मिक स्थल:** यहाँ माँ शाकुम्भरी देवी शक्तिपीठ, भूतेश्वर महादेव मंदिर और बागेश्वर महादेव मंदिर जैसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थल स्थित हैं।

राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय

कहा- शुद्धिकरण भी छुआछूत का दूसरा रूप, देश में संविधान-संघ की लड़ाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में आज भी दो विचारधाराओं संविधान और आरएसएस की विचारधारा की लड़ाई है।

राहुल गांधी ने देश में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और दावा किया कि देश में करोड़ों दलितों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि दशकों तक दलितों के साथ अत्याचार हुआ जो आज तक खत्म नहीं हो सका है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दशकों तक दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है और आज भी हो रहा है। चाय की दुकान पर दलितों के लिए अलग कप रखा जाता है और अभी भी शादी में दलितों को घोड़े पर चढ़ने पर पीटा जाता है। स्कूलों में दलितों से सफाई कराई जाती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाती है। उन्होंने कहा कि जितना सफल दलित होता है, उतना बड़ा प्रहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि 8 अगस्त 26 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद, श्री राम सेना के सदस्यों ने कथित तौर पर उसी स्थान पर शुद्धिकरण हवन किया। शुद्धिकरण करने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को न्याय मिलना चाहिए।

टॉक्सिक के फ्लॉप होने की केआरके ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी

फिल्म की रिव्यू पर एक्टर ने एक्स पर डाली पोस्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। अपनी एक्टिंग व बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर कमाल राशिद खान अर्थात केआरके फिल्म टॉक्सिक के रिव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि फ़िल्म

टॉक्सिक बुरी तरह फ्लॉप होगी। क्योंकि जब किसी हीरो के आस-पास 10 हीरोइनें हों, तो वह फ़िल्म पर ध्यान नहीं दे सकता। ये रिव्यू इस बात का सबूत हैं कि यह फ़िल्म शुक्रवार तक भी नहीं टिक पाएगी। अपने साफगोई के लिए फिल्मी दुनिया में मशहूर कमाल राशिद खान ने इससे पहले भी कई रिव्यू दे चुके हैं। वह क्रिटिक बनकर दूसरी फिल्मों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते है। इससे पहले वह सलमान खान की फिल्म राधे, सरबजीत सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मे बताई थी।

वह अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैकसन स्टारर फिल्म 2.० को कचरा बताया था। ऐसा ही कु छ मोहनजोदड़ो,साहो व छिछोरे के लिए उन्होंने लिखा मैं रिव्यू के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की हालत में नहीं हूं।

क्यों कम हो रही है जियो प्लेटफार्म्स में कर्मचारियों की संख्या

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। जियो का कारोबार बढ़ रहा है ग्राहक बढ़ रहे हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जियो प्लेटफार्मस का हेडकाउंट लगभग 21 फीसदी घटकर 27,935 रह गया। उसी समय कंपनी का ग्राहक आधार 52 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। सवाल यह भी कि क्या यह इफिशेंसी की कहानी है या रोजगार की बदलती तस्वीर?

ये सवाल भी जोर शोर से उठा

52 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों वाली कंपनी और करीब 28 हजार कर्मचारियों का आंकड़ा अपने आप में बहस पैदा करता है। और अगर द्ध भविष्य में इंसानों के काम का बड़ा हिस्सा संभालने वाला है तो जियो की घटती वर्कफोर्स को केवल एक संख्या मानकर छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जियो अब सिर्फ मोबाइल कंपनी नहीं रहना चाहती क्योंकि जियो क्लाउड, जियो एआई, जीपीयू कम्प्यूटिंग और एआई कंजीटिव सर्विसेज की पेशकश कर रहा है। जियोब्रेन 5जी और एआई/एमएल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

यानी कंपनी की नजर केवल टेलीकॉम के अगले पांच साल पर नहीं बल्कि एआई और क्लाउड इकॉनमी के अगले दौर पर है। और यहीं इस स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जियो आईपीओ असल में टेलीकॉम कंपनी की लिस्टिंग है या भारत के अगले एआई और डिजिटल साम्राज्य को बाजार से वैल्यू दिलाने की तैयारी? अगर दूसरा जवाब सही है तो निवेशक को और ज्यादा सावधान होना चाहिए। क्योंकि एआई की कहानी आज दुनिया की सबसे गर्म निवेश कहानियों में है। लेकिन एआई बोल देने से हर कंपनी एआई कंपनी नहीं बन जाती। एआई में पैसा लगता है डेटा सेंटर चाहिए और जीपीयू चाहिए, बिजली चाहिए, नेटवर्क चाहिए, क्लाउड चाहिए, रिसर्च चाहिए, प्रतिभा चाहिए और सबसे बढ़कर चाहिए लगातार भारी पूंजी निवेश।

हमारा काम सिर्फ आगह कर देना

मीडिया का काम खबर देना है बाजार का काम कीमत तय करना है लेकिन निवेशक का काम फैसला करना है और फैसला करते समय एक बात याद रखिए कंपनी का नाम आपका पैसा नहीं बताता रिलायंस का इतिहास शानदार हो सकता है जियो का विस्तार अभूतपूर्व हो सकता है ग्राहक आधार विशाल हो सकता है मुनाफा बढ़ रहा हो सकता है एआई का भविष्य चमकदार हो सकता है। फिर भी सवाल पूछिए कि आईपीओ का पैसा कहां जाएगा? कर्ज कितना है? कर्ज क्यों चुकाया जा रहा है? कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? कमाई के मुकाबले वैल्यूएशन उचित है या नहीं? मुनाफे का कितना हिस्सा कारोबार में वापस जाएगा? डिवेडेंट पालिसी क्या है? कर्मचारियों की संख्या क्यों घटी?

नाम देखकर पैसा मत लगाइए भीड़ देखकर पैसा मत लगाइए

जियो का आईपीओ आएगा तो उत्साह आएगा। शोर आएगा। टीवी स्टूडियो सजेंगे। बाजार विशेषज्ञ आएंगे। भविष्य की कहानियां सुनाई जाएंगी। आप सुनिए लेकिन खरीदने से पहले कैलकुलेटर निकालिए क्योंकि नाम देखकर पैसा मत लगाइए भीड़ देखकर पैसा मत लगाइए विज्ञापन देखकर पैसा मत लगाइए एआई सुनकर पैसा मत लगाइए रिलायंस देखकर भी पैसा मत लगाइए पहले पूछिए मेरे 100 रुपये के बदले कंपनी मुझे वास्तव में क्या दे रही है? यही सवाल आपको निवेशक बनाता है। बाकी सब आपको सिर्फ ग्राहक बनाता है।

मंगला एक्सप्रेस में पैंट्रीकार का खाना खाने से 30 छात्र बीमार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से केरलम के एर्नाकुलम जा रही मंगला एक्सप्रेस में शुक्रवार देर रात करीब 30 स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हुई। जिसमें 5 बच्चों की हालत गंभीर हो गई।

इस घटना के बाद हड़कंप मच गया, प्रशासन ने आनन-फानन में ट्रेन को खंडवा स्टेशन पर रोककर सभी बच्चों का इलाज कराया गया। रात ट्रेन को खंडवा स्टेशन पर करीब 50 मिनट के लिए रोका गया। रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तत्काल स्टेशन पर पहुंचकर बच्चों को प्राथमिक उपचार कर दवाएं दीं। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से बीमार 5 बच्चों सहित सभी यात्रियों को यात्रा के लिए आगे रवाना कर दिया गया।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4** पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**